(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय और विदेशी पर्यटकों को इन पर्यटक-स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिये विमान सेवाओं के किराये में छूट देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी0एम0 इब्राहीम) : (क) जी, नही।

(ख) यह प्रश्न नही उठता। (ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स अन्य अनेक रियायतों/छूटों के अलावा, 15 अथवा अधिक यात्रियों के समूह के लिए टूर कंडक्टर की 100% तक की छूट तथा डालर टैरिफ पर विभिन्न छूटें अर्थात अन्तर्देशीय और भारत-नेपाल सैक्टर पर 25% की युवा छूट, 21 दिन के टूर के लिए 750 अमरीकी डालर तक डिस्कवर इंडिया किराया, उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी स्टेशन समूहों के अन्दर यात्रा हेतु 300 अमेरीकी डालर का इंडिया वंडर किराया तथा सार्क देशों के बीच व्यक्तियों के लिए 20% और समूहों के लिए 30% सैर-सपाटा किराये संबंधी पेशकश कर रही है।

(ड) यह प्रश्न नही उठता।

Policy regarding FDI inflow

1060. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Govemment have framed any policy regarding an annual Foreign Direct Investment (FDI) inflow;

(b) if so, the broad features thereof;

(c) whether the Reserve Bank of India's study is openly sceptical of FDI inflows, talking of the irrelevance of further liberalisation;

(d) whether his Ministry has at any strage considered the results of the impact study of FDI on two major dynamic aspects of development, technological capacity and export promotion; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VERENDRA KUMAR): (a) and (b) The Government's policy towards Foreign Direct Investment (FDI) is to encourage a larger flow of FDI especially in priority sectors such as infrastructure and export potential industries. The Common Minimum Programme has shown a target of an annual inflow of $ 10 billion to be achieved in future.

(c) The RBI's study, while commending the current policy, has observed that liberalisation of foreign investment and technology (foreign collaboration) policies is not the sole determinent of FDI inflows. The broader economic environment in the host country is a supplementary factor.

(d) and (e) The RBI's study mentions that, within the limitations of the sample period, the results of its impact study of FDI indicate that technology transfer is only one element of technological capability building and, by itself, is not adequate to ensure the dynamics of technological progress. Technological capability building in a developing country is a combined process of technology import from external sources, domestic R&D and the relationship between the two. Technology import can stimulate or substitute domestic technology efforts. The study notes that a significant positive impact on export by firms having foreign collaboration is not visible, presumably because of the current attractiveness of the large and growing Indian market.

राज्यों की आर्थिक स्थिति

1061. **श्री नरेन्द्र मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा वे दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों से 31.12.96 की स्थिति के अनुसार 15040 करोड़ रुपया बकाया के रूप में वसूलना है,

(ख) किस राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार का कितना-कितना रुपया कब-कब से बकाया है तथा इस संबंध में वर्ष –वार ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) केन्द्र सरकार इस रुपये की वसूली के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) संविधान के अंतर्गत राज्य स्वायत्त है और राज्य का वित्तीय प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है जिसके लिए वह अपनी-अपनी